POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

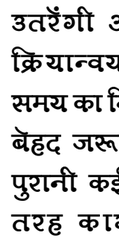

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2016-17 का बजट रखा। बजट में ग्रामीण स्तर तक शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व स्वच्छता, जैसी बुनियादी जरूरतों को अहमियत दी गई है।

बजट में इस बार किसान व खेती की दशा सुधारने पर खास जोर दिया गया है। किसानों को जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाने, युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं रोजगार दिलाने, स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण विकास को तवज्जो देने और नागरिकों के हितों का खयाल रखने जैसे वादों को पूरा करने का बजट में सपना संजोया गया है।

कुल मिलाकर बजट तभी अच्छा कहा जा सकेगा, जब घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी और उनका समय पर सही क्रियान्वयन हो जाएगा। इसके लिए समय का निर्धारण और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। नहीं तो यह बजट भी पुरानी कई घोषणाओं व योजनाओं की तरह कागजी पुलिन्दा बन कर रह जाएगा। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में देश की आर्थिक सेहत को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण विकास को पंख लगाने, आम उपभोक्ता को सशक्त बनाने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार सृजन तथा खेती और किसान के विकास को खास प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ाने का जो सिलसिला बन रहा है, वह एक अच्छा संकेत है। इस बार मनरेगा के लिए ज्यादा राशि का आवंटन किया गया है। लेकिन इसके माध्यम से पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कालेधन पर लगाम लगाने के प्रयास भी किए गए हैं।

कुल मिलाकर बजट में कई सुधार सामने आए हैं, जो देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने और बहुआयामी विकास को नई दिशा देंगे। आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप में समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

किसानों की दशा सुधारने पर दिया जोर

केन्द्रीय बजट में किसानों की दशा सुधारने और कृषि उत्पादन की दिशा बदलने पर खासा जोर रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस साल 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे प्राकृतिक आपदा के कारण किसान को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसान कल्याण के लिए 35984 करोड़ रुपए का आवंटन करते हुए वित्त मंत्री ने भरोसा जताया है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए किसानों को ई-बाजार से जोड़ा जाएगा।

इस साल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नाबार्ड को समर्पित एक दीर्घावधि सिंचाई निधि बनाई जाएगी। इसके अलावा 9.5 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण व 35 हजार 984 करोड़ रुपए का कृषि व किसान विकास के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। कृषि विकास योजना की शुरुआत करते हुए जैविक खेती का दायरा बढ़ाया गया है। अब 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती होगी।

संकट में सरकार किसानों के साथ

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के बजट में किसानों को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा है कि आगामी वर्ष में किसानों को 40 हजार नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। बजट में खाद, बीज, बिजली, और हरित खेती पर किसानों को खास अनुदान देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ है।

नई प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए 676.37 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। किसानों के लिए भूमि विकास बैंकों से ऋण की ब्याज दर घटाकर 5 से 2 फीसदी की गई है। फसली ऋण योजना के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना व ग्रीन हाउस विकास के लिए भी अनुदान बढ़ाया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर टैक्स कम करने से किसानों को राहत मिल सकती है। किसानों को फसल के सही दाम मिल सके इसके लिए ई-मण्डी शुरू होगी। इससे किसान ऑन लाइन उपज बेचने का सौदा कर सकेंगे।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

एंटीबायोटिक के बारे में हों जागरूक

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर 'कट्स' द्वारा जयपुर में 'प्रतिजैविक पदार्थों से मुक्त भोजन' विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के प्रोफेसर डॉ. निर्मल के. गुरवानी ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं की अधिकता के बारे में उपभोक्ता एवं कंपनी दोनों को जागरूक होना होगा। इनके ज्यादा उपयोग से मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और शरीर में मौजूद मित्र वायरस धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक गुप्ता ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाइयां मरीज को उसकी जरूरत के हिसाब से ही लिखी जानी चाहिए। कार्यशाला में उपभोक्ता विभाग के उप निदेशक संजय झाला, राजस्थान विश्वविधालय की होम साइंस विभाग की प्रोफेसर डॉ. कनिका वर्मा, 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, उपभोक्ता संस्थाओं व मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गांवों में होगा अब तेजी से विकास

केन्द्रीय व राज्य बजट में मजबूत ग्रामीण विकास का सपना संजोया गया है। वित्त मंत्री जेटली ने जहां गांवों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया है वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खासतौर पर मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, ई-पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू करने का एलान किया है। इसके तहत लोगों को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए 15 लाख 378 हजार 98 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। गांवों में सूक्ष्म एवं लघु दर्जे के उद्योगों व खादी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी पंचायत मुख्यालयों पर नियत दिवस पर पंचायत शिविर के जरिए ग्रामीण जनता के काम पंचायत स्तर पर निपटाए जाएंगे। ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इन ग्राम सभाओं में 2.45 लाख युवा कौशल विकास योजना से जुड़ चुके हैं।

महिलाओं के लिए खोला पिटारा

इस बार बजट महिला दिवस के मौके पर रखा गया। इसी दिन वसुंधरा राजे का जन्म दिन भी था। शायद इसीलिए महिलाओं को जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कई योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का ऐलान किया गया है। जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक बालिकाओं को 50 हजार रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। लेकिन उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ना आवश्यक होगा।

सरकार बालिकाओं के पालन-पोषण पर भी पूरा ध्यान देगी। सामूहिक विवाह पर प्रत्येक वधु को दिया जाने वाला अनुदान 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। प्रदेश में 30 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर करीब 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 5.75 लाख बीपीएल परिवार की महिलाओं के खातों में 2000 रुपए जमा कराए जाएंगे।

उद्योगों में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए भू-रूपान्तरण छूट को 50 से बढ़ाकर 100 फीसदी किया गया है। महिला युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 400 रुपए, मिनी कार्यकर्ता के मानदेय में 300 रुपए व आशा, साथिन व सहायिका के मानदेय में 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बालिका संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। पालनहार योजना के लिए बजट में 171 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

गांवों तक सड़कें, पहुंच होगी आसान

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। राज्यों के हिस्से मिलाकर यह राशि 27 हजार करोड़ रुपए होगी। वर्ष 2019 तक 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण से 65 हजार गांव सड़कों से जुड़ेंगे। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राजस्थान के बजट के मुताबिक प्रदेश में 8 हजार 803 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 250-350 तक की आबादी की 1468 बस्तियां सड़कों से जुड़ेंगी। इसके लिए 1618 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 142.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सेहत का ख्याल-नब्ज पर हाथ

केन्द्रीय बजट में स्वस्थ महिला व सुरक्षित परिवार पर खास ध्यान दिया गया है। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के जरिए प्रत्येक परिवार को सालाना एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा देने का वादा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें 30 हजार रुपए की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। जरूरतों को देखते हुए हर जिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डायलिसिस सुविधा की शुरुआत की जाएगी।

राजस्थान के बजट में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को खास तवज्जो दी गई है। ई-हैल्थ कार्ड को भामाशाह बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। 13.10 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में अस्पतालों का भवन निर्माण किया जाएगा। छोटे अस्पतालों का रूप बदला जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मजबूती के लिए 1718.12 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

कमजोर वर्ग को दिया सम्बल

केन्द्र सरकार ने नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में प्रति परिवार एक लाख रुपए तक हैल्थ कवर, डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, एससी व एसटी को गांव में बिजली के साथ डिजिटल साक्षरता जैसे कई परिलाभ देने का वादा बजट में किया है। अनुसूचित जाति कल्याण व समाज कल्याण के मद में 4911 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। कुपोषण को रोकने के लिए पोषाहार पर 1570 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

वहीं राज्य सरकार के बजट में खाद्य सुरक्षा योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सभी जिलों में 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने, आवास सुविधा मुहैया कराने के साथ-साथ उनके फायदे के लिए कई घोषणाएं भी की हैं, जिन्हें भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा।

पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट में शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। शिक्षा के लिए 23 हजार 177 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 445 स्कूलों में अतिरिक्त भवनों का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्कूलों में बिजली व पानी की दुरुस्त व्यवस्था करने के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कई सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत कराने के साथ ही उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेशभर में सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाएगा। कौशल विकास के लिए 20 नए संस्थान खोलने का भी एलान किया गया है। स्कूल दूर होने पर लड़कियों के आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था होगी। छात्राओं के लिए लेपटॉप, स्कूटी व साइकिल योजना को लागू रखा गया है।

हुनर से जोड़कर दिलाएंगे रोजगार

केन्द्र सरकार उद्योग और अकादमी की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड का गठन करेगी। इसके जरिए 3 साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। देशभर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। मनरेगा के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट 38 हजार 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।

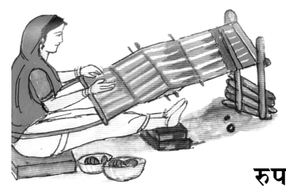

राज्य सरकार के बजट के अनुसार ग्राम सभाओं से कौशल विकास के लिए 2.45 लाख युवाओं का चयन किया जाएगा। युवाओं द्वारा लिए गए कौशल ऋण पर 6 फीसदी तक ब्याज में सहायता दी जाएगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए 354 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर